श्री राजनाथ सिंह

का

अध्यक्षीय भाषण

भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय परिषद बैठक

2-3 मार्च 2013, ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली

“

आज का युवा ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत को नई ऊंचाइयों तक देखना चाह रहा है। मैं यह मानता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने युवा सन्यासी के रूप में 19वीं शताब्दी में भारत के स्वाभिमान को जो वैश्विक प्रतिष्ठा या Global recognition दिया था उसके आधार यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानन्द आधुनिक इतिहास के प्रथम युवा थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को समझा और उसके अनुरूप अपने विचारों को विश्व के पटल पर रखा। So Swami Vivekanand was the first global youth of modern India.

राजनाथ सिंह
अध्यक्ष, भाजपा

”

अध्यक्षीय उद्‌बोधन
राष्ट्रीय परिषद बैठक
दिनांक–2,3 मार्च 2013, नई दिल्ली

मित्रों, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व पुनः ग्रहण करने के बाद देश के कोने कोने से आये आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं प्रथम बार मिल रहा हूं। यह एक सुखद संयोग है परन्तु दायित्यबोध की अनुभूति देता है। सुखद इसलिए कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थिति हमारे मन को सुख की अनुभूति देती है। दायित्वबोध इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं और देश की जनता की हमसे अपेक्षायें ऐसे अवसरों पर हमें हमारे सम्मुख चुनौतियों का पुनः स्मरण कराती हैं।

मित्रों इस राष्ट्रीय परिषद का समय दो ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी है। एक तीर्थराज प्रयाग में महाकुम्भ का पर्व चल रहा है और दूसरा स्वामी विवेकानंद के जन्म की 150वीं वर्षगांठ, जिसका उत्सव सारा देश मना रहा है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि मानवजाति के लिपिबद्ध इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। इसकी विराटता और निरंतरता भारतीय राष्ट्र की सनातन जीवनी शक्ति का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने एक युवा सन्यासी के रूप में 1892 में मात्र 29 वर्ष की आयु में अमेरिका में भारतीय धर्म और दर्शन का जो उद्‌घोष किया था उसने पूरे भारत की चेतना को एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। इसके द्वारा भारत ने इतिहास की नयी करवट बदलनी शुरू की थी जिसके संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में (पेज–337) पर लिखा Vivekananda came as a tonic to the depressed and demoralized Indian mind and gave it self-reliance and some roots in the past.'

आज का युवा ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत को नई ऊंचाइयों तक देखना चाह रहा है। मैं यह मानता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने युवा सन्यासी के रूप में 19वीं शताब्दी में भारत के स्वाभिमान को जो वैश्विक प्रतिष्ठा या Global recognition दिया था उसके आधार यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानन्द आधुनिक इतिहास के प्रथम युवा थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को समझा और उसके अनुरूप अपने विचारों को विश्व के पटल पर रखा। So Swami Vivekanand was the first global youth of modern India. अतः यह अवसर हमें युवा शक्ति की ऊर्जा के साथ उस आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्पंदन भी देता है, जो कि भाजपा के राजनैतिक दर्शन और वैचारिक अधिष्ठान का आधार है।

परन्तु इसके साथ कुछ दुखद यादें भी जुड़ी है। महाकुम्भ में मौनी अमावस्या के दिन अनेकों तीर्थयात्री हताहत हुए, और अभी कुछ दिन पूर्व हैदराबाद में हुए बम धमाकों में अनेकों बेगुनाह भी हताहत हुए। मैं पूरी भाजपा की तरफ से प्रयाग एवं हैदराबाद में मारे गये एवं घायल हुए सभी व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और संवेदनायें व्यक्त करता हूं।

मित्रों पिछले कुछ महीनों में भाजपा के लिए जो कुछ सुखद समाचार आए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात विधानसभा चुनावों में हमारी विजय। यह भाजपा की लगातार चौथी विजय है। इस बार की यह जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि गुजरात के अत्यन्त लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह भाजपा की दो–तिहाई बहुमत के साथ लगातार तीसरी विजय है। यदि लम्बे समय तक सत्ता में रहने का मौका मिले तो भाजपा और अन्य दलों में शासन करने की क्षमता में क्या अन्तर है, नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात इसका एक उदाहरण बन चुका है। इस हैट्रिक के लिए हम सभी श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनन्दन करते है।

मित्रों, हम भारत के मुख्य प्रतिपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं और देश के सामने आज गम्भीर चुनौतियां है। देश की जनता इन चुनौतियों का समाधान के लिए हमारी तरफ देख रही है।

देश का आम आदमी चिंताओं से ग्रसित है। रोज़मर्रा की उसकी जिन्दगी दूभर होती जा रही है। देश के अन्दर और सीमाओं पर और बड़ी–बड़ी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। **कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार से देश क्षुब्ध है, निराश है, हतोत्साहित है और क्रुद्ध है। वह परिवर्तन चाहता है। विकल्प की तलाश में है।**

वर्तमान परिस्थितियों में यूपीए–2 का विकल्प भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ही है। अनुकूल समय है बस हमसे अनुकूल आचरण की अपेक्षा है।

श्रद्धेय अटल जी की सक्रियता न होने पर भी, परम आदरणीय आडवाणी जी के शीर्ष मार्गदर्शन में, कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम और अपने लोकप्रिय एवं सक्षम सहयोगी नेताओं के रण–कौशल से हमें विजय अवश्य मिलेगी। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं दिखता है।

देश की वर्तमान स्थिति

मित्रों, आज देश की जो दशा है वह दशा नहीं बल्कि एक दुर्दशा है उसके एक नहीं अनेक आयाम है। आर्थिक कुप्रबंधन, महंगाई, भ्रष्टाचार, अक्षम प्रशासन, दिशाहीन नीतियां, विफल कूटनीति एवं लचर आंतरिक व बाहरी सुरक्षा आदि किसी भी क्षेत्र पर नजर डाले तो एक बेहद निराशा जनक तस्वीर दिखाई पड़ती है।

यदि सर्वप्रथम राष्ट्र की सुरक्षा की बात की जाय तो

सुरक्षा के खतरे

पिछले महीने की 22 तारीख को हैदराबाद में बम विस्फोट हुए जिसमें करीब 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब सौ लोगों को आंशिक या गम्भीर चौटें आई। लेकिन यह इस देश की पहली आतंकवादी घटना नहीं है। आज भारत में ऐसा कोई बड़ा शहर नही है जो आतंकवादियों के निशाने पर नहीं।

यू.पी.ए. शासनकाल में लगातार एक के बाद एक आतंकी घटनायें इस देश में हुई है लेकिन मुम्बई हमले में मौके पर पकड़े गये कसाब को छोड़कर एक भी मामले में घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सजा नहीं मिल पाई है।

आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष को बड़ा झटका यू.पी.ए. सरकार ने तब दिया जब

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2008 में मुम्बई हमलों के बाद अपनायी गई Zero tolerance towards Terrorism' की अपनी ही नीति का मिस्र के शर्म–अल–शेख शहर में जाकर परित्याग कर दिया। यू.पी.ए. सरकार ने 'शर्म अल शेख' में जाकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को भी भारत की ही तरह 'आतंकवाद से पीड़ित' देश कह डाला।

यू.पी.ए. सरकार ने आतंकवाद पर पाकिस्तान से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद 'दोस्ती मुकर्रर' रखने की जो इकतरफा कवायद की है उससे भारत की छवि एक 'Soft State' के रूप में उभरी है। जब तक सरकार आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा रवैया नहीं अपानएगी आतंकवादी लगातार बढ़े हुए मनोबल के साथ इस देश के शहरों, ट्रेनों, बसों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहेंगे।

आतंकवाद मानवता के खिलाफ की गई सबसे अमानवीय अपराध है। आतंकवाद को न तो विचारधारा के स्तर पर, न मजहब के स्तर और न ही किसी और व्यवस्था से विरोध के Justification के रूप में स्वीकारा जा सकता है और न ही इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार में गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे ने जयपुर में जो कहा वह अनायास ही नहीं कहा था। कांग्रेस पार्टी जानबूझ कर आतंकवाद के मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देकर 'वोट बैंक की राजनीति' कर रही है। गृहमंत्री ने भले ही संसद का सत्र बचाने के लिए अपने बयान पर माफी मांगी है मगर कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है। बाटला हाउस एनकाउंटर का विषय हो अथवा 26/11 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश करार देने वाली तथ्यहीन पुस्तकों का विमोचन हो, **कांग्रेस के नेता हमेशा से राष्ट्रवाद की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करते दिखे हैं। इसकी पराकाष्ठा तो तब हुई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के गांव जा कर आंसू बहाते रहे, पर वे भारत की सीमा पर पाकिस्तान की फौज के द्वारा शहीद हुए और जिनके सिर काट लिये गये ऐसे सैनिकों के गांव जाने की फुरसत नहीं निकाल सके।** मैं, सुषमा जी और नितिन जी स्वयं उस गांव गये थे और हमने उसी पीड़ा को देखा है।

'हिन्दू आतंकवाद' की बात करके यू.पी.ए. सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर कर दिया हैं। इसी यू.पी.ए. सरकार ने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में लश्कर की भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर अमरीकी सरकार ने 'लश्कर' पर प्रतिबंध लगाया था। मगर अचानक राजनीतिक कारणों से अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए यू.पी.ए. सरकार ने भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ दी। मित्रों, आतंकवाद का न कोई मजहब होता है और न कोई रंग। **भाजपा आतंकवाद को किसी भी प्रकार का मजहबी रंग देने के पूरी तरह खिलाफ है।**

यू.पी.ए. सरकार की इस गलती का इतना बड़ा खामियाजा भारत को उठाना पड़ रहा है कि जब गृहमंत्री ने संघ–भाजपा पर आंतकवाद का प्रशिक्षण देने की बात कही तो लश्कर का प्रमुख हाफिज सईद सबसे अधिक खुश हुआ और हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम–घूम कर भारत को 'आतंकी देश' ठहराने की कोशिश में लग गया। पाकिस्तान को भारत पर आतंकवाद के विषय पर ऐसा आक्षेप लगाने का मौका स्वयं यू.पी.ए. सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते दे दिया। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए न तो वैचारिक रूप से और न ही मानसिक रूप से तैयार है। केवल भाजपा ही आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में सक्षम है।

आन्तरिक सुरक्षा के लिए दूसरा बड़ा खतरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की समस्या है। वोट बैंक की राजनीति के चलते अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हालात काफी नाजुक है। पिछले साल असम में जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई उसकी जड़ में अवैध घुसपैठ की समस्या है।

बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का झुंड पूर्वोत्तर राज्यों का न केवल Demographic profile बदल रहा है बल्कि इन इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों (हिन्दू–मुसलमान दोनों शामिल है) के साथ आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हिंसा पर उतारू है। आई.एम.डी. टी. एक्ट पर अपना फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी घुसपैठ भारत पर आक्रमण के समकक्ष है। अतः बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनना चाहिए और पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर का अधिकांश इलाका दूसरे देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है अतः यहां विदेशी सीमा प्रबन्धन के विषय में एक व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए।

असम में हुई हिंसा के बावजूद यू.पी.ए. सरकार ने अभी तक सबक नहीं लिया है। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में हिंसक घटनाएं हो रही है। अन्य राज्यों में भी भारतीयों एवं अभारतीयों के बीच गाहे बगाहे हिंसा का दौर जारी है। यदि यू.पी.ए. सरकार इसे संज्ञान में नही लेगी और अवैध घुसपैठ पर लगाम नहीं कसेगी तो पूर्वोत्तर जल उठेगा।

बांग्लादेशी घुसपैठ भारत की सुरक्षा के लिए एक और समस्या है। औपचारिक रूप से Group of Ministers report on reforming national security system (2001) के अनुसार भारत में डेढ़ करोड़ बांग्लादेशी थे। अब 12 वर्ष बाद आप संख्या का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में असम में हुई हिंसा बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को मिलने वाली चुनौती की एक बानगी प्रस्तुत करती है। अब बांग्लादेशी असम के अलावा, त्रिपुरा, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में फैलते जा रहे हैं।

आतंकवाद की भांति देश में नक्सलवाद भी आन्तरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तो नक्सलवाद को देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी मानते है। इसके बावजूद नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र कम नहीं हो रहा है और आए दिन नक्सली हिंसा में हमारे सुरक्षा बलों के जवान मारे जा रहे है।

नक्सलवाद की चपेट में देश के करीब 250 से अधिक जिले लगभग देश का आधा भूभाग नक्सली प्रभाव के अन्तर्गत है। नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने के लिए यू.पी.ए. सरकार को कड़ी इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में यू.पी.ए. सरकार ने Integrated Action Plan के अन्तर्गत अभी तक केवल 78 जिलों को शामिल किया है। इस Action Plan को देश के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है।

नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक समेकित नीति की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा बलों के उपयोग के साथ–साथ इन क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का समाधान भी प्रस्तुत करना होगा। नक्सली समस्या को बौद्धिक समर्थन देने वाले अतिवादी वामपंथी बुद्धिजीवियों

को भी बौद्धिक स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

एक और आयाम आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा है कि यह आतंकी संगठन अक्सर नशीली दवाओं की तस्करी द्वारा धन कमाते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2011 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2004 में भारत में लगभग 28 लाख लोग ड्रग्स के एडिक्ट थे। इनमें से अधिकाशंतः 15 से 35 आयु वर्ग के थे। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का ड्रग्स का आदी होना भविष्य में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

आतंरिक सुरक्षा और आतंकवाद की एक नई चुनौती जाली नोटों के रूप में भी इस देश में पांव पसार रही है। यह समस्या यूपीए सरकार के आने के बाद विशेषकर 2006 से उतरोत्तर गंभीर होती जा रही है। National Investigation Agency (NIA) के अनुसार भारत में लगभग 16 हजार करोड़ के जाली नोट चल रहे हैं। जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

आन्तरिक सुरक्षा का एक और आयाम जो सामान्यतः अभी बहुत गंभीरता से सामान्य जनता में समझा नहीं जाता है वह है साइबर आतंकवाद। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक और गंभीर चुनौती है इसे Next generation threat की संज्ञा दी जा रही है। यह हमारे लिए भविष्य में बहुत चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार भारत साइबर आतंकवाद के शिकार होने की दृष्टि से विश्व के पांच प्रमुख निशानों में से एक है। **यह समस्या किस गति से बढ़ रही है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2004 में साइबर अटैक की 23 घटनायें रजिस्टर हुई थीं तो 2011 में 13301 घटनायें रजिस्टर हुई थी।** भारत में संचार, रेल और वायु यातायात, स्टॉक एक्सचेंज और मिलिट्री कमान जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है।

साइबर क्राइम किस तरह देश का माहौल बिगाड़ सकता है इसका उदाहरण पिछले वर्ष देखने को मिला। गत वर्ष इंटरनेट पर दुष्प्रचार करके पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़काने का जो प्रयास हुआ उसके चलते देश भर में हिंसा हुई। यह साइबर वारफेयर के द्वारा देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सामने आने वाले नये प्रकार के खतरों को दर्शाता है।

एन.सी.टी.सी का विषय

केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए केन्द्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (National Counter Terrorism Center) NCTC के बारे में हैदराबाद की घटना के बाद जो पहल की है वह ईमानदारी से होनी चाहिए मगर भारत के संघीय ढ़ांचे के मूल आधार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस सरकार का आतंकवाद की समस्या के प्रति जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वह ईमानदारी का नहीं रहा है। इतनी बड़ी समस्या के बाद भी गुजरात और मध्यप्रदेश के आतंकवाद विरोधी कानूनों को ठण्डे बस्ते में डाल रखा है। **यदि सरकार आतंकवाद के विषय पर इतनी गंभीर है कि वह एन.सी.टी.सी. के जैसा एक केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी संस्थान बनाना चाहती है तो मुझे आश्चर्य है कि वो केन्द्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी कानून क्यों नहीं बनाना चाहती। आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास कोई भी आतंकवाद विरोधी कानून नहीं है।** एन.सी.टी.सी. पर हम अपना पक्ष विस्तार से संसद में रख चुके हैं।

बाह्य सुरक्षा

आंतरिक ही नहीं वाह्य सुरक्षा के लिए सेना को जैसी तैयारी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है क्योंकि रक्षा सौदों में एक के बाद एक हो रहे भ्रष्टाचार के चलते सेना को उचित और आवश्यक हथियार भी नहीं मिल पा रहे हैं। पूर्व थलसेना अध्यक्ष ने भी सेना की इन आवश्यकताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। वायुसेना में बहुत से उपकरण पुराने और तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नही है। इस हेतु सरकार को ध्यान देना चाहिए मगर सरकार ने इसके विपरीत सेना के बजट में भी कटौती कर दी। जबकि भारत आंतरिक और वाह्य सुरक्षा दोनों की दृष्टियों दुनिया के सर्वाधिक संवेदनशील देशों में एक है।

पड़ोसी देश

भारत की स्थिति एक दृष्टि से दुनिया में बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण है, विश्व में आतंकवाद का सबसे बड़ा केन्द्र भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है और भारत के साथ उसके संबन्धों का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। भविष्य तो और भी चिन्ताजनक दिखाई पड़ रहा है। 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी एवं नाटो सेनाओं की वापसी के बाद इस क्षेत्र की स्थिति भारत के लिए बहुत अधिक चिन्ताजनक होने वाली है।

अफगानिस्तान से अमरीकी और नाटो फौजों की वापसी के बाद पाकिस्तान और कट्टरपंथी ताकतों का दखल अफगानिस्तान में पुनः बढ़ सकता है। भविष्य में इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सामरिक परिदृश्य पर केन्द्र सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध सिर्फ व्यावसायिक स्तर तक ही रहेंगे। अथवा उसमें कोई रणनीतिक पक्ष भी जोड़ा जायेगा।

पाकिस्तान के साथ हमारी नीति कितनी लचर है कि 28 जुलाई 2005 को जौनपुर में हुई ट्रेन धमाके जिसमें 13 लोग मारे गये थे, से लेकर हाल ही में हुए हैदराबाद विस्फोटों तक, भारत में हुई अनेक आतंकवादी वारदातों में सैकडों लोग मारे गये। अनेक घटनाओं में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिले हैं।

हम कितने साट स्टेट हैं कि इन दर्जनों वारदातों में सिर्फ 26/11 के हमलों में कसाब को सजा हो पायी है। बाकी जगह तो सरकार की जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पायी। हां गाहे–बगाहे सरकार उसमें भगवा रंग डालने का राजनैतिक प्रयास अवश्य करती रहती है।

पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवादियों के प्रशिक्षण, हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की तस्करी, जाली नोट और इंटरनेट पर सांप्रदायिक दुष्प्रचार आदि क्षेत्रों में जो बहुआयामी युद्ध लड़ रहा है उसे Hybrid War कहा जा सकता है। अमेरिका के एक प्रमुख रणनीतिकार फ्रेंक हॉफमैन ने Hybrid War की एक नई अवधारणा दी है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी लड़ाई जिसके अनेकों आयाम हो और उसका हर समय सही अंदाज लगाना मुश्किल हो। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बिल्कुल उचित बैठता है। अतः इससे लड़ने के लिए भारत को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एक व्यापक योजना बनानी होगी। परन्तु दुर्भाग्यवश यू.पी.ए. सरकार इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान के साथ एक लचर और दब्बू विदेश नीति पर चल रही है। शर्म–अल–शेख से लेकर हैदराबाद तक यह कमजोर विदेश नीति साफ दिखती है।

दूसरी तरफ अन्य देश आतंकवाद के प्रति एक स्पष्ट एवं आक्रामक नीति रखते हैं। उसे मैं एक

उदाहरण से व्यक्त करना चाहूंगा। जब पाकिस्तान की धरती से अमरीका में आतंकी हमला होता है तो प्रतिक्रिया में अमरीकी राष्ट्रपति संकल्प लेते हैं कि We will find you and finish you और पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन को समाप्त कर देते है। यदि इजराइल पर कोई आतंकी हमला होता है तो इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं We will hunt you down. We will annihilate you फिर प्रतिक्रिया में अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हैं। और हम पाकिस्तान से लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया देते है कि We will not play cricket अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगे। क्या देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी विदेश नीति का इससे लचर और त्रासदीपूर्ण उदाहरण कहीं मिल सकता है।

चीन की गतिविधियां भी हाल के वर्षों में चिंताजनक रही है। चीन द्वारा हाल ही में कराची के पास ग्वादर में डीप नेवल बेस का नियंत्रण किया जा रहा है। पाक अधिकृत काश्मीर में 11 हजार सैनिकों का अड्डा बनाया जा रहा है। हालांकि चीन इससे इंकार करता है। परन्तु यह एक कूटनीतिक सत्य है कि पाकिस्तान और चीन में एक "All weather friendship" है। पाकिस्तान के अलावा चीन श्रीलंका में हमबमटोटा में नौसैनिक अड्डे का निर्माण करवा रहा है। मालद्वीव में चीन की अत्यधिक सक्रिय तथाकथित व्यवसायिक गतिविधियां कहीं न कहीं यह संकेत देती है कि भारत के तीनों तरफ के समुद्रों पर चीन अनेक संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है। ब्रहमपुत्र पर बांध बनाना हो जिससे कि चीन इंकार करता है परन्तु उपग्रहों के चित्र इसकी पुष्टि करते हैं। बांग्लादेश को प्रचुर मात्रा में हथियार देना हो अथवा ल्हासा से काठमांडू तक सड़क बनाने का प्रयास, यह सब चीन द्वारा भारत की रणनीतिक घेराबंदी के स्पष्ट संकेत है, जिसे यू.पी.ए सरकार केवल मूकदर्शक बनी देख रही है।

श्रीलंका के साथ भी अब हमारे सम्बन्ध उतने मुधर नहीं रहे हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित Palk Strait में समुद्री सीमा पर अक्सर श्रीलंका की जल सेना द्वारा मछुआरों को प्रताड़ित करने की घटनाएं होती हैं। यू.पी.ए. सरकार को भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और उनके आजीविका के अधिकार का संरक्षण करना चाहिए। भारत सरकार को अपनी कूटनीतिक दक्षता का प्रयोग करके श्रीलंका में तमिलों के पुर्नवास और संविधान संशोधन के द्वारा तमिलों को सत्ता में भागीदारी के श्रीलंका के वचन को पूरा करवाने का प्रयास करना चाहिए।

बांग्लादेश के साथ भारत सरकार तीस्ता जल बंटवारे के साथ 'Enclaves' के आदान–प्रदान का जो कार्य करने का विचार कर रही है उसमें भारत को तेरह हजार एकड़ भूभाग छोड़ना पड़ेगा जबकि बांग्लोदश को महज तीन हजार एकड़। इस दस हजार एकड़ की भरपाई कैसे होगी सरकार इसका कोई उत्तर नहीं दे रही है।

मालद्वीव में तख्ता पलट का विषय हो या **नेपाल** में आंतरिक अस्थिरता, केन्द्र सरकार भारत के सभी पड़ोसी देशों के प्रति एक दिशाहीन कूटनीतिक विदेशनीति की शिकार दिखती है।

विदेश नीति

यदि अब अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी उपस्थिति एक महाशक्ति के रूप में दर्ज करना चाहता है तो हमें अपनी विदेश नीति बहुत सुदृढ़ और युक्तिसंगत करनी होगी। जिसका एक उदाहरण है एनडीए शासन काल का अटल जी के नेतृत्व में जब हमने अणु बमों का परीक्षण किया

था और अंततः न्यूक्लियर पॉवर के रूप में हमें मान्यता मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने नवम्बर 2010 में भारत की संसद में यह कहा था : India is not emerging, it has emerged तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के emerge होने की शुरूआत उसी दिन 13 मई, 1998 को हो गयी थी जिस दिन पोकरण विस्फोट हुये थे। ओबामा का कथन एनडीए सरकार की सुदृढ़ और सफल विदेश नीति के दूरगामी परिणाम का प्रतीक है।

एन.डी.ए. के समय तक भारत आर्थिक विकास की दर में भी सही उपलब्धियां कर रहा था। हमने जब यूपीए को सत्ता सौंपी तो जीडीपी आठ दशमलव चार पर पहुंच गया था। लेकिन आज वही पांच पर पहुंच रहा है।

आज जब ग्लोबलाइजेशन का दौर है और किसी भी देश की शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति से आंकी जाती है तो यह आवश्यक है कि हमारी कूटनीति, विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति के साथ तारतम्य स्थापित करके बनाई जाये। आज का युग केवल Strategic diplomacy का नहीं बल्कि आज की कूटनीति Economic diplomacy के बगैर पूरी नहीं हो सकती। भारत सरकार कूटनीति के इस आयाम को विशेष महत्व नहीं दे पा रही है।

विदेश नीति के बारे में भाजपा एक नये आयाम के बारे में दृष्टि रखती है जो भविष्य में भारत के प्रभाव को अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होगा। भारत की विदेश नीति में एक एकांगी पक्ष रहा कि हम पश्चिम की ओर देखते रहे और इसलिये अब पूर्व की ओर देखने की बात कही जाती है जिसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। यदि हम पूर्व की ओर नजर डालें तो चीन और जापान के अतिरिक्त उत्तर कोरिया, बर्मा, थाईलैण्ड, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ भारत का भौगोलिक, राजनैतिक ही नहीं बल्कि शताब्दियों पुराना एक सांस्कृतिक संबंध है। इन देशों से हमारा सांस्कृतिक बन्धुत्व (Cultural brotherhood) है। अतः इस क्षेत्र में भारत को इन देशों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए Cultural element का प्रयोग करना चाहिए।

आर्थिक कुप्रबंधन

आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने भारत को महाशक्ति बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किया था, वर्तमान सरकार के मौद्रिक, आर्थिक कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार ने इस मार्ग में स्पीड ब्रेकर की तरह रोक लगा दी।

आज जी.डी.पी. गिर रहा है, वित्तीय घाटा और वाणिज्यिक घाटा बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, रूपया कमजोर हो रहा है, निवेशकों का अर्थव्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत की रेटिंग लगातार कम हो रही है। कुल मिलाकर कहां जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी साख पर बट्टा लग गया है।

डालर के मुकाबले रूपया ही नहीं डूब रहा है बल्कि इसी के साथ भारत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास भी डूब रहा है। एन.डी.ए. के शासन काल में जहां भारत विदेशी निवेशकों के लिए चीन के बाद सबसे आकर्षक स्थल था, वह स्थिति मौजूदा हालात में बिल्कुल उटल गई है। During NDA regime it was said that it is an era of Indian success story, now in UPA regime it is said that era of Indian success story is over.

मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने 2009 के चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने के सौ दिन के अंदर मंहगाई को पूरी तरह काबू में कर देंगे। क्या हुआ उस वायदे का। आज सत्ता में 9 वर्ष रहने के बाद वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2013 में मुद्रास्फीति (इनलेशन) 6.62 पर था। इसके आधार पर सरकार ने यह दावा किया कि मुद्रास्फीति 38 महीनों के निम्नतम स्तर पर आ गई। **वास्तविकता तो यह है कि औद्योगिक उत्पादों के दाम गिर रहे हैं और पर्याप्त आपूर्ति की कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। अतः आम आदमी को सीधे प्रभावित करने वाली खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी 2013 में बढ़ कर 11.88 प्रतिशत हो गई है।**

वित्तमंत्री ने बजट में कहा कि देश का राजकोषीय घाटा 5.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस आधार पर सरकार गैस और डीजल पर सब्सिडी घटा रही है। अब हालत यह हो गये हैं कि भारत में अमरीका ही नहीं पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में सबसे मंहगा पेट्रोल बिकता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जबकि, हम अपनी जरूरत का 30 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खुद पैदा करते हैं। पैट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती इन कीमतों ने शहरी मध्य वर्ग की कमर तोड़ दी है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत नये बजट में महंगाई और मंदी इन दोनों से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः महंगाई और अधिक बढ़ने की संभावना है। उत्तरी और पूर्वी राज्यों में जो धन आवंटन किया गया है वह आवश्यकता से बहुत कम है। रेल बजट में जिस प्रकार से रेल किरायों को डीजल पेट्रोल के माध्यम से बाजार से जोड़ दिया गया है उससे अब रेल के किराये निरन्तर बढ़ते रहेंगे।

इसके अतिरिक्त यू.पी.ए. सरकार ने सत्ता में आने के बाद ब्याज दरों को लगातार बढ़ाना शुरू किया। तर्क यह दिया गया कि इससे महंगाई नियंत्रित होगी परन्तु हमने देखा कि ब्याज दर और महंगाई दोनों लगातार बढ़ते गए। इस कारण उद्योग जगत की पूरी व्यवस्था चरमरा गई और बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ने लगी।

एन.डी.ए. के शासनकाल में हम प्रचुरता (Surplus) की अर्थव्यवस्था थे, यू.पी.ए. के शासनकाल में अभाव (Deficit) की अर्थव्यवस्था बन गये हैं। Today we need to restart the engine of our economy.

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI in Retail)

यूपीए सरकार ने भारत के मझोले और छोटे व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए तमाम सामाजिक और राजनीतिक दलों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का मंजूरी दिलवा दी। सरकार ने इसे पास कराते समय जो सब्जबाग दिखाए है वो यर्थाथ से परे हैं। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपनी देश की जनता से छोटी दुकानों से खरीदारी करने का आग्रह कर रहे है। फिर भी यह मान रहे है कि एफ.डी.आई. सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। यर्थाथ तो यह है कि इससे भारत के छोटे दुकानदार बर्बाद हो जायेंगे, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा और तमाम लोगों को बेरोजगारी मिलेगी। **भाजपा छोटे और मध्यम दुकानदारों के हितों की रक्षा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और यदि हमारी सरकार बनी तो इसके लिए भविष्य में जो भी कदम उठाने होंगे वह हम उठायेंगे।**

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इण्डो–यू.एस. न्यूक्लियर डील को जुलाई 2008 में पास कराते समय सरकार ने कहा था कि भारत की ऊर्जा समस्या का समाधान हो जाएगा पर साढ़े चार साल बाद ऊर्जा की क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि गत वर्ष जुलाई में ग्रिड फेल होने के कारण पूरे भारत को दो दिन का अंधकार मिला। ऐसा ही कुछ भविष्य में एफ.डी.आई. के पक्ष में किए जा रहे दावों का भी होगा।

भ्रष्टाचार

यूपीए सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के ऐसे काले अध्याय इस सरकार ने लिखे हैं जिसमें एक निश्चित प्रवृत्ति या *डेफिनिट पैटर्न* साफ़ नज़र आता है। वह है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो और किसी तरह एनडीए सरकार की तरफ तार जोड़ दो।

सबसे ताज़ा *ऑगस्टा वेस्टलैन्ड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील* है। इटली में इस हेलीकॉप्टर कम्पनी के सीईओ को भारत में घूस देने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है।

आश्चर्य है कि इटली में वह अधिकारी पकड़ा जाता है, लेकिन भारत में उस कमीशन को लेने वाला कौन है, इसका भेद यूपीए सरकार को नहीं मालूम है। या मालूम है तो वो खामोश रहना चाहती है। ग्यारह महीने तक सरकार चुप्पी साधे रही और हेलीकॉप्टर कम्पनी को क्लीन चिट भी दे दिया। लेकिन जब ये बातें सार्वजनिक हुई तो यूपीए सरकार ने तत्काल अपनी निश्चित प्रवृत्ति के अनुसार पैंतरा बदलते हुए यह झूठा आरोप लगाया कि ये सौदा 9 साल पहले हट चुकी एनडीए सरकार के दौरान तय हुआ था।

यदि Indo-US Nuclear deal से CWG, Commonwealth, 2G और Augasta-Westland Helicopter तक हर विषय की नीति NDA सरकार ने बनायी थी तो आप क्या पिछले 9 सालों से भजन कर रहे थे। **यदि एनडीए सरकार ने कुछ नई नीतियां बनायी भी थीं तो उस नीति में अनीति तो आपने की हैं और अब आप केवल राजनीति कर रहे हैं।**

रक्षा मंत्री जी कहते है कि 'Nobody will be spared'। यह कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे है मगर मुझे शक है कि रक्षा मंत्री जी और यू.पी.ए. सरकार के रहते हुए कानून के हाथ उस ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे जहां इस हेलीकॉप्टर डील के तार जुड़ें है। यदि सरकार ईमानदारी से इस भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा देना चाहती है तो उसे केवल जे.पी.सी. से जांच की खानापूर्ति नहीं बल्कि इस संदर्भ में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करके आपराधिक जांच करवानी चाहिए।

यूपीए सरकार की इस भ्रष्ट अनीति के चलते कभी एनडीए के शासनकाल में IT Hub और knowledge based economy के लिये जाना जाने वाला भारत आज भ्रष्टाचार के लिये जाना जाने लगा है।

आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सारे विश्व में हमारी साख पर जो बट्टा लगा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज हमारी गिनती दुनिया के भ्रष्टत्तम देशों में होने लगी है। ट्रांसपैरेंसी इन्टरनैशनल ने अपने Corruption perception index में भारत को भ्रष्टाचार के बाबत 94वें स्थान पर रखा है। सन् 2007 में पहली बार भारत को 180 भ्रष्ट देशों में 72वां स्थान पर रखा गया था। वर्ल्ड बैंक के Country performance and institutional assessment में भी भारत को भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है।

वर्ल्ड बैंक के ही "Doing Buisness Index" में भारत को 183 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रखा गया है। भारत की इस सूची में हान्डुरास और गाज़ा पट्टी जैसे क्षेत्रों से भी पीछे है केवल नाईजीरिया और सीरिया से ऊपर है।

दुनिया में म्यानमार, सूडान, अफगानिस्तान, सोमालिया और नार्थ–कोरिया भ्रष्टाचार के निचले पायदान पर हैं। अगर अपने यहां भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो खतरा ये है कि भारत इन देशों के साथ उसी पायदान पर स्थान पाएगा जो सबसे अधिक भ्रष्ट देश की खिताब हासिल कर चुके हैं।

हमारा यह आरोप है विगत् नौ वर्षों में भ्रष्टाचार के इस दानवीय विस्तार के लिए मुख्यतः कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आज कांग्रेस सरकार इस कदर भ्रष्टाचार में रच बस गयी है कि इस सरकार ने तो अब्राहम लिंकन की प्रजातंत्र की परिभाषा देने वाली उस युक्ति को ही मानो बदल दिया है। मेरा मानना है कि This government is by the corruption, of the corruption and for the corruption.

मित्रों, अक्सर भारत में लोग नामराशियों की चर्चा करते है। कहीं न कहीं प्रकृति किसी भी समस्या का निदान उसी नामराशि के अक्षरों में निहित कर देती है। जैसे **राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, ओबामा ने ओसामा को मारा वैसे हमें विश्वास है कि करप्शन भी कांग्रेस को अवश्य मारेगा।**

मित्रों, इकोनोमिक्स में एक सिद्धांत होता है Opportunity Cost इसका अर्थ होता है कि जिस काम में धन प्रयोग हो रहा है यदि उसकी बजाय किसी वैकल्पिक कार्य में प्रयोग होता तो उसका मूल्यांकन भी Cost के निर्धारण में होना चाहिए। यदि हम घोटालों में लगे धन पर Economics कर यह सिद्धांत लगा कर देखें तो पता लगेगा कि हमने इस भ्रष्टाचार की जो कीमत चुकाई है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा है।

कोयला आवंटन, टू–जी स्पैक्ट्रम, खाद्यान्न घोटला आदि में जनता के जो लाखों करोड़ों रूपये लूटे गये हैं यदि उनका यही उपयोग हुआ होता तो उससे पूरे देश के सारे गांव और सारे शहर अच्छी सड़कों से जुड़ चुके होते, सभी को बिजली मिल चुकी होती। हजारों अस्पताल और स्कूल खुल चुके होते। कई विश्व स्तरीय तकनीकी संस्थान और सेना को सैकड़ो किस्म के नये हथियार प्राप्त हो चुके होते। अतः *मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि भ्रष्टाचार नही हुआ होता तो यह देश अब तक महाशक्ति बन चुका होता।* *परन्तु इसके उलट वर्तमान सरकार ने अपनी भ्रष्ट नीतियों के चलते आज देश के आम जनमानस को एक ऐसी प्रतिक्रियात्मक मनः स्थिति (रिएक्सनरी स्टेट ऑफ माइंड) में डाल दिया है कि आज पूरा समाज मानो ज्वालामुखी पर बैठा हो, इसे रोकना होगा।*

सरकार की पूरी आर्थिक प्रगति को यदि कि Mathematical formula में व्यक्त करना हो तो इस सरकार की आर्थिक नीति को 8/9, 4/5 फार्मूले के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आप पूछेंगे कि यह फार्मूला क्या है। एन.डी.ए. सरकार के समय विकास दर 8/9 प्रतिशत क आसपास थी और महंगाई दर 4/5 प्रतिशत के आसपास थी। यू.पी.ए. सरकार के 8/9 वर्ष के शासनकाल में फार्मूला उलट गया है। मंहगाई दर बढ़कर 8/9 प्रतिशत से अधिक और विकास दर लुढ़ककर 4/5 प्रतिशत के आसपास आ गई है।

भाजपा और एन.डी.ए. की राज्य सरकारों ने भी विकास दर के शानदार कीर्तिमान बनाये।

यदि केन्द्र में हमारी सरकार आई तो हम इस बार 9 या 10 प्रतिशत के विकासदर का लक्ष्य नहीं रखेंगे, बल्कि हम बड़े विराट लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी आर्थिक नीतियां बनायेंगे। 21वीं सदी में जिसे दुनिया एशिया की सदी मान नहीं है भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो हमें चीन को ध्यान में रखकर नीति बनानी होगी। आज चीन का जीडीपी लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर और भारत का 1. 8 ट्रिलियन डॉलर। हमारी आर्थिक नीतियां इस भारी अंतर को ध्यान में रखकर निर्धारित होनी चाहिए।

आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में ही नहीं कृषि के क्षेत्र में भी यू.पी.ए. सरकार के शासनकाल में घोटाले की खबरें आ रही है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार 2008 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी योजना में जम कर भ्रष्टाचार हुआ है।

मीडिया के हवाले से पता चला है कि 3.5 करोड़ किसानों के लिए बनाई गई इस योजना में CAG ने व्यापक गड़बड़ी/धांधली पाई है जबकि उसने महज 90000 किसानों की audit की। राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में मैं मांग करता हूं कि 2008 में किसानों को कर्ज माफी के नाम पर जो घोटाला CAG की प्रारंभिक जांच में उजागर होने की खबरें आई हैं उसकी जांच करायी जाए और किसानों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को दण्डित किया जाए।

गरीब और किसान

भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र आज यह है कि एन.डी.ए. सरकार के जाने के समय जो विकासदर थी वह आज लुढ़ककर उसके आधे के आसपास आ गई है। अमीर और गरीब का अंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्र New York Times (May 5, 2012) ने भी अपने आलेख "Never mind Europe, worry about India". में स्पष्ट रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा "What is disturbing is that much of the decline in growth rate is unevenly distributed with gratest burden falling on poors. The problem of Euro Zone is pittance by comparison."

भारत में अमीर–गरीब की बढ़ती खाई New York में बैठे लोगों को दिख रही है पर New Delhi में बैठे लोगों को नहीं दिख रही है। भारत सरकार गरीबी रेखा के आंकड़े को 32 और 26 रुपए के आधार पर छिपाने का काम करने में लगी है। मैं सरकार में बैठे नेताओं से कहना चाहूंगा कि गरीबी के विषय पर संवेदना के साथ काम करिए। सांख्यिकी के साथ नहीं। **गरीब के दर्द को आंकड़ों में नहीं बल्कि गरीब की आंखों में देखने की कोशिश करिए।**

वित्त मंत्रालय की हाईपावर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश में यह कहा गया था कि देश के 98 प्रतिशत उद्योग असंगठित क्षेत्र में हैं। लेकिन इतने बड़े समूह को बैंकों के ऋण का केवल 1.4 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था का चिंतन ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि गांव के किसान, सड़क के रिक्शा चालक, मजदूर ढाबा चलाने वाले वर्ग तक भी विकास की किरण पहुंचे।

वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां देश की जनता के सबसे बड़े वर्ग के व्यवसाय कृषि के प्रति बहुत उपेक्षापूर्ण एवं संवेदनहीन रही है। औसतन हर 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है।

खेती पर आश्रित देश की 70 प्रतिशत आबादी बहुत दयनीय स्थिति में है।

इस देश का 58 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा के आसपास गुजारा करता है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिड़ी देता है। वहीं कृषि प्रधान कहा जाने वाला भारत ऐसी आर्थिक नीति पर चल रहा है जो खेती को अनुत्पादक सैक्टर मानकर कृषि से अन्य व्यवसायों में पलायन को प्रोत्साहन दे रही है। पिछले एक दशक से प्रति व्यक्ति कृषि उपज 1 प्रतिशत के औसत वार्षिक विकास दर पर स्थित है। खेती के लिए उपयुक्त 1250 लाख हेक्टेयर जमीन में पिछले 30 वर्षों में एक इंच की भी वृद्धि नहीं हुई है। इसके बावजूद कृषि, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2011 में 45.5 प्रतिशत कार्यबल कृषि में लगा था।

पिछले 30 वर्षों से कृषि उत्पादन की 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए 2010 में आस्ट्रेलिया में 10.8 टन प्रति हेक्टेयर चावल उत्पन्न होता था जो कि भारत के 3.3 प्रति हेक्टेयर से 3 गुना अधिक है।

भारत की 40 प्रतिशत आबादी जो 13 से 35 वर्ष की आयु के बीच है उसका दो तिहाई हिस्सा गांव के बीच रहता है। अतः युवा भारत के विकास का संकल्प कभी भी इन दो तिहाई युवाओं की अनदेखी करके पूरा नहीं हो सकता।

भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ और बसे घना बसा मैदान है। अतः हमारी आर्थिक नीति हमारी इस प्राकृतिक क्षमता या Natural Potential को ध्यान में रखकर बननी चाहिए।

विश्व में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के बावजूद आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता खाद्यान्न है। भारत में विश्व के खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र बनने की क्षमता है। 21वीं सदी में यदि हम भारत को विश्व का नेतृत्व करते देखना चाहते हैं, तो हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, अथवा इंटलेक्चुअल कैपिटल ही नहीं बनाना होगा क्योंकि इसके दावेदार तो बहुत देश हैं, अपितु इनके साथ–साथ भारत को विश्व की एग्रीकल्चर कैपिटल बनाना होगा। क्योंकि भौगोलिक, प्राकृतिक, मानव संसाधन एवं परम्परागत दृष्टि से यह क्षमता सिर्फ भारत के पास है।

हमारा यह संकल्प है कि यदि हमें केन्द्र की सत्ता मिली तो हम भारत को 21वीं सदी में विश्व की Intellectual Capital के साथ–साथ विश्व की Agriculture Capital के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

यह बात हमारी कार्यशैली में भी दिख रही है। हमारी राज्य सरकारों ने कृषि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है। गुजरात में जहां हर किसान के पास मिट्टी की गुणवत्ता का कार्ड है, गुजरात एकमात्र राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, सभी किसानों को Soil Card मिले हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दर को 18.96 प्रतिशत तक के रिकार्ड स्तर तक पहुंचाया। कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने वाले राज्य बने इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में हमारी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एवं कर्नाटक आदि राज्य सरकारों ने जो काम किये हैं उनका विवरण हमारे मुख्यमंत्रीगण देंगे।

मित्रों, मैं इस देश का कृषि मंत्री रहा हूं। मुझे किसानों के दर्द को नजदीक से देखने का मौका मिला है। यदि हमें सत्ता में आने का मौका मिला तो हम प्रयास करेंगे कि –

- किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं बल्कि उनकी आमदनी का बीमा हो। यदि हमें सत्ता मिली तो हम 'कृषि आमदनी बीमा योजना' को लागू करेंगे।
- खाद्यान्न सुरक्षा बिल को और अधिक व्यावहारिक बनायेंगे और छत्तीसगढ़ मॉडल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेंगे।
- भूजल एवं सिंचाई की समस्याओं के उचित समाधान के लिए हम एक राष्ट्रीय जल नीति बनायेंगे।
- कृषि ऋण की नीति का पुनःनिर्धारण करेंगे।
- दुग्ध उत्पादन एवं डेरी उद्योग को प्राथमिकता देंगें।
- पंजाब हरियाणा में जहां रासायानिक उर्वरकों के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई है वहां भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने वाले माइक्रो न्यूट्रेंट्स को उचित दामों पर उपलब्ध करायेंगे।
- गांव के स्तर पर बिजली और पानी के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ओर बायोगैस जैसे प्रावधानों के उपयोग के लिए एक समेकित नीति (Integrated Policy) बनायेंगे।
- और कृषि क्षेत्र में यथासंभव जैविक खेती (Organic farming) को बढ़ावा देंगे। और स्वदेशी तकनीकी जैसे System of Rice Intensification (SRI) System of wheat intensification (SWI) द्वारा उत्पादन किये जाने वाले चावल और गेहूं को बढ़ावा देंगे जिसमें कम पानी, जैविक खाद का प्रयोग होता है और ळड ज्मबीदवसवहल के बगैर कृषि होती है। प्रारंभिक परीक्षणों में इसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं

महिला के प्रति बढ़ते अपराध

दो महीने पहले दिसम्बर माह में राजधानी दिल्ली में एक युवती के साथ हुए जघन्य बलात्कार की घटना ने पूरे देश की संवेदनशीलता को जागृत किया है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट के बाद केन्द्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिस पर सदन में चर्चा होनी है।

भाजपा का यह मत है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में यदि पीड़ित महिला की मृत्यु होती है या वह आजीवन विक्लांगता का शिकार होती है तो अथवा ऐसिड फेंक कर शारिरीक विकृति लाने जैसे मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए।

महिलाओं के प्रति अपराध केवल कठोर कानून से ही नहीं थमेंगे। इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। पहला पुलिस और प्रशासन के स्तर पर क्रियाशीलता और संवेदनशीलता बढ़े, दूसरा समाज में भी एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे महिलाओं की भी पूरी सहभागिता हो और तीसरा स्तर है हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा और संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक बने।

युवा

भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। पूरी दुनिया के सर्वाधिक युवा भारत में है। भारत के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साटवेयर जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है।

परन्तु एक दूसरा सत्य भी है कि भारत का दो–तिहाई युवा गांवों में रहता है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बंगाल और बिहार के पिछड़ें इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा और नक्सली प्रभाव में आने वाला सबसे बड़ा वर्ग भी युवा ही है।

कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में युवाओं की समस्या बहुत विविधतापूर्ण है। परन्तु सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है क्योंकि यही वह पहली समस्या है जिसका लाभ उठाकर युवाओं को अपराध और आतंकवाद की तरफ आसानी से खींच लिया जाता है।

एन.डी.ए. सरकार के समय रोजगार सृजन को बहुत प्राथमिकता दी थी। आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक रोजगारों का सृजन एन.डी.ए. के शासनकाल में हुआ था यू.पी.ए. सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। यदि विकास की दर 5 प्रतिशत रह जाती है तो करोड़ों युवाओं के बेरोजगार होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

एक अन्य पक्ष जो युवाओं के साथ जुड़ा है वह है कि नैतिक मूल्यों में आ रही कमी। दिल्ली का गैंगरेप केस भी कही ना कही उसी खतरे को दिखा रहा है। सरकार और समाज दोनों को युवाओं में भारतीय एवं नैतिक मूल्यों के प्रति झुकाव लाने का कोई सुनियोजित प्रयास करना चाहिए।

भारत में शरणार्थी

भारत में पिछले दिनों बड़ी संख्या में पाकिस्तान से भाग कर वहां रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों ने यहां शरण ली है। भारत में कोई सुविचारित शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास नीति न होने के कारण भारत आने वाले शरणार्थियों को बड़ी अनिश्चितता के वातावरण में जीवन जीना पड़ता है।

शरणार्थी नीति बनाते समय घुसपैठिए और शरणार्थियों के मध्य विभेद करते हुए एक उचित नीति बनाने की आवश्यकता है। भारत ऐतिहासिक काल से अनेक पीड़ित समूहों की शरण स्थली रहा है। परन्तु इस आड़ में घुसपैठ को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। **जो न्यायसंगत शरणार्थी है, और जो प्रताड़ित होकर आ रहे हैं उनके संदर्भ में स्पष्ट विभेद करते हुए एक विशिष्ट शरणार्थी पुनर्वास नीति बनाई जानी चाहिए। यदि हमारी सरकार बनी तो हम एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक शरणार्थी नीति बनायेंगे।**

जम्मू–कश्मीर

जम्मू काश्मीर में जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर आतंकवाद के द्वारा लोकतंत्र का घोटने का प्रयास किया जा रहा है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार न केवल पंचायतों को वित्तीय सहायता देने मे आनाकानी कर रही है बल्कि सरपंचों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कराने में विफल रही है। पिछले एक साल में कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों द्वारा कई सरपंचों की हत्या की गई और उन्हें सरेआम धमकाया गया कि वे अपनी सरपंची त्याग दे। आतंकवादियों के भय से सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिए हैं। सरपंच सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकर कोताही बरत रही है। मैंने प्रधानमंत्री को इस बावत पत्र लिखा मगर यू.पी.ए. सरकर ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है।

जम्मू काश्मीर विधान सभा में 111 सीटें हैं। परन्तु चुनाव सिर्फ 87 सीटों पर होता है क्योंकि 24 सीटें पाक अधिकृत काश्मीर के क्षेत्र में आती हैं। यह व्यवस्था 1952 से चल रही है। हमारा

यह मानना है कि उन 24 रिक्त सीटों को नामांकन के द्वारा पाक अधिकृत काश्मीर क्षेत्र से विस्थापित लोगों के बीच से भरे जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

तेलंगाना एवं पृथक राज्यों का मुद्दा

तेलंगाना के निर्माण को लेकर आन्ध्र प्रदेश में कई सालों से जनान्दोलन चल रहा है मगर यू.पी. ए. सरकार द्वारा जानबूझ कर इसकी अनदेखी की जा रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने तेलंगाना के निर्माण के प्रति वचनबद्धता दिखाते हुए 28 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की थी। इसके बावजूद तेलंगाना का सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार नक्सली समूहों और हैदराबाद में सक्रिय जेहादी समूहों के प्रति उतनी सख्त नही दिखती है जितनी सख्त तेलंगाना आंदोलन को कुचलने के लिए दिखती है। **हम तेलंगाना की जनता की भावना को समझते है और यदि केन्द्र में NDA की सरकार होगी तो तेलंगाना राज्य का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।**

हमारी राज्य सरकारें

यूपीए सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। देश की जनता को अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की बातें अतीत के एक स्वर्णिम युग की तरह याद आती हैं। आज भी भिन्न–भिन्न राज्यों में हमारी राज्य सरकारों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकास और कुशल प्रशासन के अनेक कीर्तिमान बनाये हैं।

छत्तीसगढ

कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य के जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है। विकास दर के मामले में छत्तीसगढ़ देश के सबसे अग्रणी चार राज्यों में है। 2009–10 में छत्तीसगढ़ की विकास दर 11.49 प्रतिशत थी, जो उस वर्ष देश में सर्वाधिक थी। कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास दर में भी छत्तीसगढ़ देश के पांच सबसे अग्रणी राज्यों में था। हमारी सरकार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 350 यूनिट से बढ़ कर 15.47 यूनिट प्रति वर्ष हो गई।

खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके अन्तर्गत प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी को खाद्यान और प्रोटीन की सुरक्षा का लाभ मिला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छत्तीगढ़ ने देश में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है।

कर्नाटक

मित्रों, कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली भाजपा बनी। विगत चार वर्षों में भाजपा की कर्नाटक सरकार ने अनेक शानदार कार्य किये हैं। इन्फ्रास्ट्रैक्चर और आई.टी. के साथ–साथ कृषि क्षेत्र में कर्नाटक के इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची विकास दर प्राप्त की। किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण दिलाने वाला एवं 2011–12 में अलग कृषि बजट देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना। इसके चलते कर्नाटक राज्य को वर्ष 2011 में कृषि के क्षेत्र में National Award for Leadership in Agriculture मिला।

रोजगार के लिए दक्षता पैदा करने की दृष्टि से दक्षता आयोग बनाने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना। हमे पूरा विश्वास कि आगामी विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए पुनः सरकार बनाने में सफल होगी।

बिहार

बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद जिस ढंग से हालात बदले हैं सारा देश उसका गवाह है। बिहार में कई अद्वितीय काम हुए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार 11.95 प्रतिशत की विकास दर के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने कृषि से जुड़े 18 विभागों को मिलाकर एक कृषि कैबिनेट बनाया। और एक कृषि रोडमैप भी बनाया। कृषि से जुड़ी नीतियों के चलते नालंदा जिले में एक किसान ने 22 टन प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया जो कि पहले चीन के नाम था।

पंजाब

पंजाब की एनडीए सरकार आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि पंजाब का एक साम्प्रदायिक वातावरण जिसे कांग्रेस ने बहुत दूषित कर दिया था। हमारी आने के बाद उसे सामान्य करके विकास की दिशा में नये कदम बढ़ाये हैं। कृषि उत्पादन में अपने शानदार प्रदर्शन को कायम रखते हुए आधारभूत संरचना और उद्योगों में भी पंजाब सरकार ने विकास के नये कीर्तिमान बनाये हैं। इसी के चलते पंजाब के इतिहास में पहली बार हमारी सत्ता में पुनः वापसी हुई है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। हमारी सरकार आने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ चुकी है। कृषि विकास की दर को मध्य प्रदेश ने 19 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर तक पहुंचाया। 24 घंटे बिजली देने की क्षमता विकसित करने वाला मध्य प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'लाडली लक्ष्मी योजना' पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। निश्चित समय में निर्णय उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा प्रदाय गारंटी अधिनियम बनाया। सौ से अधिक सेवायें इसके दायरे में लाई गयी। विश्व बैंक ने इसकी सराहना की और संयुक्त राष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से मध्य प्रदेश ने सांस्कृतिक महत्व की एक अनूठी और सराहनीय योजना प्रारंभ की है।

गोवा

गोवा की हमारी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ी योजनाओं के साथ–साथ विकास के कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य को कम करने वाला देश का पहला राज्य है। लाडली लक्ष्मी योजना और गृह आधार योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया गया है। शत–प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है। नव कामधेनू सुधारित योजना के तहत दूधारु गायों के खरीद पर नब्बे प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के लिए लोकायुक्त बिल पास किया जा चुका है।

गुजरात

हमारी गुजरात की सरकार ने तो विकास के ऐसे कीर्तिमान बनाये हैं जिसकी सराहना भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हुई है। गुजरात ने एक पारदर्शी और सक्षम प्रशासन की मिसाल कायम की है। गुजरात देश का पहला राज्य है जहां सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हुई। अब सभी को

स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। विगत 11 वर्षों से लगातार कृषि विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही है। सभी किसानों के पास स्वायल कार्ड है और चिरंजीवी योजना के माध्यम से हर गर्भवती महिला को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त है।

गुजरात के कुशल प्रशासन की सराहना यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरीकी कांग्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में की है। गुजरात भाजपा के लिए एक गौरव का प्रतीक बन चुका है।

श्रीराम सेतु

हाल ही में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि रामसेतु मुद्दे पर स्वयं सरकार द्वारा गठित आर.के. पचौरी की रिपोर्ट सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के विचार को गंभीर तथ्यों के आधार पर खारिज करती है।

आर.के. पचौरी समिति ने सेतुसमुद्रम प्रौजेक्ट को Economically और Ecologically non-viable बताया था और श्रीरामसेतु से इतर एक और Alternate route भी सुझाया था। इस समिति के अतिरिक्त भी अनेक विशेषज्ञों ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि रामसेतु टूटने से समुद्र में भारत के पास उपलब्ध बहुत सी मूल्यवान प्राकृतिक संपदा भी निकल जायेगी। सुनामी का खतरा भी और बढ़ सकता है। परन्तु सरकार इन सभी सुझावों को दरकिनार कर सेतु तोड़ने पर अड़ी हुई है।

इसके अतिरिक्त भारत धर्म की और संस्कृति में ही नहीं भारत के अस्तित्व का यह रामसेतु अविभाज्य अंग है। प्राचीन ग्रंथों में भारत के विस्तार को 'आसेतु–हिमाचल' कहा जाता है अर्थात् इस देश का विस्तार सेतु (रामसेतु) से हिमाचल तक है। यदि सेतु नहीं रहेगा तो भारत की पहचान का एक अंग भंग हो जायेगा।

यूपीए सरकार भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक मानदंडों को नष्ट करने में लगी हुई है। कितना दुखद और हास्यास्पद है कि पांच वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने न्यायालय को हलफनामे में कहा था कि राम ऐतिहासिक नहीं है। यद्यपि बाद में जनाक्रोश के चलते उसे वापस ले लिया। ऐसे ही अनावश्यक प्रश्न श्री राम जन्म भूमि के संबंध में भी उठाये जाते हैं। यह **भारत यानी राम के देश की सरकारों की सोच है और विडम्बना देखिए कि रावण के देश यानी श्रीलंका की सरकार औपचारिक रूप से भगवान राम को ऐतिहासिक मानती है और उससे जुड़े स्थलों को संरक्षित करती है।**

श्रीराम एवं रामसेतु की गरिमा पर आघात करने का ऐसा प्रयास तो गुलामी के काल में प्रत्यक्ष विदेशी शासन में भी नहीं हुआ। **जो काम अंग्रेज और औरंगजेब भी करने की नहीं सोच सके वह कांग्रेस और यू.पी.ए. करने को आमादा हैं।**

यह सरकार तर्क देती है कि 800 करोड़ लग चुके हैं इसलिये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। अरे यह सरकार लगता है कि केवल तिज़ारती सरकार रह गयी है। इस सरकार ने अपनी ईमानदारी व इकबाल तो पैसों के तराजू पर तौल ही दिया है। अब भगवान राम के प्रतीक को पैसों पर तौलने का प्रयास कर रही है। **सभ्यताओं की अस्मिता के प्रतीक कुछ करोड़ रूपयों में नहीं तौले जा सकते।**

भाजपा यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि यदि केन्द्र में हमारी सरकार आई तो न्यायालय द्वारा गठित पचौरी समिति की सिफरिशों को हम स्वीकार करेंगे। चाहे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक मार्ग चुनना पड़े अथवा उस प्रोजेक्ट को समाप्त करना पड़े, हम किसी भी कीमत पर श्री रामसेतु को टूटने

नहीं देंगे। क्योंकि यह करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का विषय है। हम श्री रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करवाने का प्रयास करेंगे।

हिन्दुत्व

हिन्दुत्व एक ऐसा विषय है जिसे लेकर भाजपा बहुत निशाने पर रहती है।

हिन्दुत्व क्या है इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगस्त 2009 में प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय पत्रिका News Week में प्रख्यात लेखिका Lisa Miller ने एक लेख लिखा था We all are becoming hindus. इसे पढ़कर आपको लगेगा कि मानो अमेरिका में लोग धर्मांतरण करके हिन्दू बन रहे हैं। परन्तु इस लेख में लिखा है कि अमेरिका में करोड़ों लोग शाकाहारी भोजन, योग, ध्यान, औषधीय चिकित्सा की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं इतना ही इस लेख के अनुसार अमेरिका में ईश्वर प्राप्ति के एक से अधिक विचार, एक से अधिक पूजा पद्धति और यहां तक कि पुनर्जन्म के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अतः अनजाने में अमेरिकी हिन्दू जीवन मूल्यों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस लेख से स्पष्ट है कि हिन्दुत्व संप्रदाय न होकर एक जीवन शैली है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के अनेक आयामों को प्रभावित कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1995 के अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दुत्व कोई मत या सम्प्रदाय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। मित्रों, यह जीवन शैली है जिसने भारत ही नहीं सारे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। जिसने संसार को बुद्ध और गांधी दिया। यही वह जीवन शैली है जो मज़हब तो छोडिए, इंसान तो छोडिए, जीव और निर्जीव में समान रूप से ईश्वर को देखती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्ममानववाद जो कि हमारा राजनैतिक दर्शन है, वह भारतीय संस्कृति के इन्हीं जीवन मूल्यों की युगानुकूल व्याख्या करता है।

हिन्दुत्व और अल्पसंख्यक

हिन्दुत्व वह जीवन शैली है जिसकी वजह से भारत में दुनिया के सारे मज़हब पाये जाते है। मित्रों, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां विश्व के सारे मज़हब ही नहीं बल्कि उनके सभी पंथ या सेक्ट्स भी पाये जाते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस्लाम में 72 फिरके हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां ये सभी 72 फिरकों को मानने वाले लोग हैं। इसाईयों में रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, सेवंथ डे एडवेंटिस, इवैंजलिस्ट ही नहीं बल्कि ईस्टर्न आर्थोडोक्स और सिरियन चर्च भारत में पाये जाते हैं। यहूदियों के साथ यदि पूरी दुनिया में कहीं अत्याचार नहीं हुआ तो वह भारत था। पारसी आज सिर्फ भारत में ही पाये जाते हैं। अतः भारत की इस साझा संस्कृति का आधार है हिन्दुत्व। और हम अपनी विचारधारा की प्रेरणा इसी से लेते हैं।

इसी भाव से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती। मैंने भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदैव इस भाव को मन में रखा। **उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब मैं समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों के साथ मुख्यमंत्री आवास में पंचायत आयोजित की थी तो मैंने अरबी और फारसी मदरसों की पंचायत भी बुलाई थी।**

इसी जीवन शैली की वजह से भारत दुनिया के ज्ञात इतिहास में एकमात्र देश है जिसने कभी

दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे अपने में मिलाने का प्रयास नहीं किया। India is the only country in the world which never went for invasion. यह वह जीवन शैली है जो व्यक्ति को दुनिया को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को जीतने के लिए प्रेरित करती है। हिन्दुत्व के बारे में भाजपा की धारणा एकदम स्पष्ट है जिसे हम सबके श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1950 के दशक में एक युवा नेता के रूप में इन पंक्तियों में व्यक्त किया था :

"हो कर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम,
मैंने तो सदा सिखाया है, करना अपने मन को गुलाम।
भू भाग नहीं शत्–शत् मनाव के हृदय जीतने का निश्चय,
हिन्दू तन–मन, हिन्दू जीवन, रग–रग हिन्दू मेरा परिचय।

भारत के भविष्य के लिए भाजपा ही क्यों

मित्रों, आज भारत युवाओं का देश है और हर युवा के मन में 21वीं सदी में भारत को महान देखने की ललक है परन्तु क्या हमारे पास वह क्षमता और वह दृष्टि है जो 21वीं सदी में भारत को महान बना सके। मित्रों, भाजपा की ओर आज सारा देश देख रहा है। कांग्रेस आजादी से पहले बनी थी, अंग्रेजों द्वारा 19वीं सदी में बनायी गई थी और कांग्रेस ने कांग्रेस 20वीं सदी में अपना शिखर देखा। भाजपा आजादी के बाद 20वीं सदी में बनी और भारत ने जब 21वीं सदी में प्रवेश किया तो भारत का नेतृत्व अटल जी के नेतृत्व में भाजपा के हाथ में था। मित्रों, **20वीं शताब्दी कांग्रेस की थी और 21वीं शताब्दी भाजपा की होगी।**

हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस को आजादी के बाद जब सत्ता मिली तो उसने गुलामी के काल की तमाम व्यवस्थाएं यथावत रखी। भारत कभी भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ सका। हम अपने राजनैतिक से लेकर आर्थिक दर्शन तक कभी रूस तो कभी अमरीका की नकल करते रहे। ज्ञान–विज्ञान के अपने परंपरागत भंडार को अंग्रेजों द्वारा स्थापित पराधीनता की मानसिकता के चलते नकारते रहे। भाजपा की विचारधारा में ही वह संभावनायें हैं जो देश को ज्ञान–विज्ञान में दुनिया से आगे ले जा सकते हैं। आज विश्व में कहा जाता है कि भारत में भविष्य विश्व बौद्धिक राजधानी 'इंटेलेक्चुअल कैपिटल' बनने की क्षमता है। परन्तु इस क्षमता के वास्तविक स्रोत को समझने की क्षमता सिर्फ भाजपा में हैं।

यह बात में किसी राजनैतिक पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आप सबके हाथ में मोबाईल फोन है और आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। यह सब तो भारत ने पश्चिम से सीखा हैं। यह ठीक है कि हमने सीख कर इसमें अच्छी महारत हासिल कर ली है पर हमने दुनिया को विज्ञान और तकनीकी में दिया क्या है। क्या हम दुनिया को कोई नई टेक्नोलॉजी देने में सक्षम है। मैं मानता हूं बिल्कुल सक्षम है। परन्तु आजादी के बाद लम्बे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने कभी Fundamental Scientific Research की तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि यह सत्य है कि विश्व का नेतृत्व वह करता है जो नई Fundamental Scientific Research निकाल कर लाता है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है जो एटम बम के आविष्कार के बाद ही महाशक्ति बना।

भारत में भी ऐसा कुछ करने की क्षमता है। मित्रों मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए

आपका ध्यान Fundamental Physics के आज हो रहे उपयोग की तरफ ले जाना चाहता हूं।

हम सभी जानते है कि आज मोबाईल से लेकर इंटरनेट और टी.वी. तक डिजिटल सिग्नल के आधार पर ही काम कर पाते हैं। डिजिटल सिग्नल को बनाना तब संभव हो पाया जब सौ साल पहले Quantum Mechanics को खोजा जा सका। Quantum Mechanics जिस सिद्धान्त से निकली वह था जर्मन वैज्ञानिक Werner Heisenberg द्वारा प्रतिपादित अनिश्चितता का सिद्धान्त Uncertainty Principal यदि हाईजन बर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धान्त न खोजा होता तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती। और डिजिटल सिग्नल और फिर उसके द्वारा आज की यह Age of Communication नही आती।

हाईजन बर्ग ने अनिश्चितता का यह सिद्धान्त भारत के वैदिक दर्शन से सीखा था। हाईजन बर्ग 1929 में भारत आए थे और रविन्द्र नाथ टैगोर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने वैदिक दर्शन और Theoretical Physics के कई विषयों पर टैगोर के साथ विचार–विमर्श किया। स्वयं हाईजन बर्ग के सहयोगी आस्ट्रियन वैज्ञानिक Fritjof Capra ने अपनी पुस्तक 'Uncommon Wisdom' में पेज नम्बर 42–43 पर ये लिखा है कि "In 1929 Heisenberg spent some time in India as the guest of the celebrated Indian poet Rabindranath Tagore, with whom he had long conversations about science and Indian philosophy. This introduction to Indian thought brought Heisenberg great vision, he told me. He began to see that the recognition of relativity, interconnectedness, and impermanence as fundamental aspects of physical reality, which had been so difficult for himself and his fellow physicists, was the very basis of the Indian spiritual traditions. 'After these conversations with Tagore,' he said, 'some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made more sense. That was a great help for me.'

और अभी पिछले वर्ष जुलाई में योरोप की CERN प्रयोगशाला में गॉड पार्टिकल खोजा गया जिसका वैज्ञानिक नाम Higgs Boson है। इसे 21वीं सदी में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि यह खोज 21वी सदी में मानव जीवन से भी ज्यादा बड़े परिवर्तन ला सकती है। इस कण की खोज का आधार भारत के महान वैज्ञानिक सत्येन्द्रनाथ बोस ने ऐसे ही सिद्धान्तों से प्रेरणा लेकर 70–80 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया है। इस कण के नाम में बोसोन शब्द सत्येन्द्रनाथ बोस के नाम से लिया गया है। एस.एन. बोस के विषय में यह कहा जाता है कि अक्सर वह मेडिटेशन अवस्था का प्रयोग भी वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में कुशलता से कर लेते थे। प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक नील्ज बोर ने भी बोस की इस क्षमता को स्वीकारा था।

आज की डिजिटल रिवोल्यूशन का सिद्धान्तिक आधार हमारे पास था और भविष्य की वैज्ञानिक क्रांतियों का आधार भी हमारे पास है। कमी केवल हमारी नीतियों में रही है कि हमने कभी भी Research of Fundamental science की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस मूलभूत शोध में हमारे परम्परागत ज्ञान का कोई आधार है यह तो हम औपनिवेशिक मानसिकता के कारण सोचने से भी डरते रहे।

यदि हमें इस देश में शासन करने का अवसर मिला तो हम मूलभूत विज्ञान एवं भारतीय विज्ञान के शोध को बढ़ावा देंगे। We will promote research in fundamental science and also research of scientific aspect of our traditional wisdom. 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले भारत का स्वरूप तभी निकल कर आयेगा जब बेसिक साइंस, बेसिक टेक्नालॉजी हमारी अपनी होगी।

Fundamental Science के शोध से हम नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी बना सकते है। इस टेक्नोलॉजी

के द्वारा हम अस्त्र–शस्त्र बनाकर रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकते है। अतः हमारी दूसरी दृष्टि भारत को रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की होगी। जिससे प्रतिरक्षा भी मजबूत होगी और आगे जाकर करोड़ों डालर के विदेशी खर्च की बचत होगी।

कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ दुनिया को भारत के योगदान के रूप में दिखाई पड़ने वाले आयुर्वेद, योग और पर्यावरण संरक्षण में नहीं बल्कि गणित और विज्ञान में भी विश्व में नई खोजें देने की क्षमता भारत के परंपरागत ज्ञान में है जिसे गुलामी के काल में हम भूल गये थे।

गुलामी के काल में बनी कांग्रेस कभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आई। अतः भारत कभी अपनी वास्तविक क्षमता को विश्व में स्थापित करने का आत्मविश्वास कांग्रेस में था ही नहीं। यदि हमें सत्ता मिली तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि भाजपा के पास वह दृष्टि है जो भारत को Intellectual capital of the world या उससे भी ऊपर जाकर पुनः 'जगदगुरु' बनवा सकती है।

वैकल्पिक अर्थव्यवस्था

हम सब देख चुके हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में साम्यवाद का पतन हो चुका है और 21वीं सदी के प्रथम दशक से पूंजीवाद लगातार लड़खड़ाता जा रहा है। आज इसी सदी में विश्व को एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। उस विकल्प का आधार केवल भारत के पास है। हमें इसे समझने की जरूरत है। इस विकल्प का आधार भारत द्वारा विश्व के इतिहास में दी गई दो सबसे बड़ी धरोहरों भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों में निहित है। बुद्ध ने जहां कहा कि सम्यक विचार और सम्यक कर्म अर्थात बुद्ध का राजनैतिक और आर्थिक दर्शन मध्यमार्ग की ओर था अर्थात् किसी भी विचार के अतिरेक में न जाना। चाहे वह पूंजीवाद हो या साम्यवाद। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना एक आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया था।

महात्मा गांधी ने तो भारत की भविष्य की व्यवस्था के लिए 1909 में ही हिन्द स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पश्चिम द्वारा प्रेरित दिशा में चलने से आने वाली समस्याओं का विवरण देते हुए कहा था कि इस दिशा में आगे चलने से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया अनेक समस्याओं से घिर जायेगी। आज हम इसे देख रहे हैं।

अतः उपभोक्तावाद के अतिरेक से बचते हुए, उपयुक्त बचने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए, प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए नैतिक मूल्यों का संरक्षण करने वाली एक नई स्वदेशी अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक विकास का वैकल्पिक मॉडल होगी। यह भूमंडलीकरण के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी कमियों को ठीक करके एक नयी दिशा सारे विश्व को देने का कार्य करेगी।

अतः 21वीं सदी के लिए भाजपा की दृष्टि अथवा विजन है कि हम

व्यय नहीं बल्कि बचत आधारित वैकल्पिक आर्थिक मॉडल (Alternative model based on savings not expenditure)

मूलभूत विज्ञान में अनुसंधान (Research in fundamental science)

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरत (Self reliant in defence production)

परंपरागत भारतीय ज्ञान जैसे जैविक, खेती और आयुर्वेद आदि में अनुसंधान (Research in traditional Indian wisdom (like organic farming & Ayurveda)

भारत को विश्व की बौद्धिक एवं कृषि राजधानी के रूप में स्थापित करना **('To make India Intellectual & Agricultural capital of the world')**

इसी दृष्टि के द्वारा भारत की गरीब और बेरोजगारी दूर होगी, भारत शक्तिशाली बनेगा और इन सबके साथ मानव जीवन के श्रेष्ठत्तम मूल्यों का प्रतीक भी बनेगा जिनके लिए भगवान राम, कृष्ण से लेकर भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी तक दुनिया भारत को जानती है।

बूथ कमेटी

भाजपा के पास एक विशाल संगठन है। परन्तु इसे नीचे स्तर तक पहुंचाना हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है। हम सब अपने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का अभियान चला रहे हैं और आने वाले समय में एक निश्चित समयावधि में हमें अपनी सभी बूथ कमेटियों का गठन कर लेना है।

कार्यकर्ता और संगठन

भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी (Cadre based party) है। आज भी देश की जनता हम सभी कार्यकर्ताओं से एक अलग एवं विशिष्ट प्रकार की मर्यादा की अपेक्षा करती है। हम सभी उत्साही कार्यकर्ता पार्टी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प रखते हैं। परन्तु राजनीति में मर्यादा और आत्मसंयम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। **राजनीति में एक सूक्ष्म बात छिपी है कि किसी व्यक्ति का राजनीति में ऊंचा स्थान केवल इसलिए नहीं बनता कि उसने क्या–क्या किया, बल्कि इसलिए अधिक बनता है कि राजनीति में रहते हुए ऐसा क्या–क्या था जो वह कर सकता था, परन्तु उसने नहीं किया।**

देश में राजनीति के आदर्श पुरूषों में से एक महात्मा गांधी ने अपनी राजनीति में इसे अमल करके दिखाया है। उनकी आत्मकथा लिखने वाले लुई फिशर ने लिखा है Gandhi greatness lay, according to his biographer Louis Fischer, was in doing what everyone else could have done but he did not. अतः हमें क्या–क्या करना चाहिए उसके साथ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हमें क्या–क्या नहीं करना चाहिए। **देश की जनता भाजपा कार्यकर्ता से यह 'न करने' वाले पक्ष पर अधिक संवेदनशील रहती है।**

संगठन की मूल इकाई कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को अपने स्वयं, संगठन, समाज और देश इन चारों के बारे में अपनी सोच स्पष्ट रखनी चाहिए। इन चारों के पक्षों में किस–किस चीज को हमें एक आदर्श संगठन का सिपाही बनने के लिए प्राथमिकता देनी है यह स्पष्ट होना चाहिए।

मेरे विचार से व्यक्तिगत स्तर पर सबसे प्रमुख तत्व जो कार्यकर्ता में होना चाहिए वह है 'संयम'। संगठन के स्तर पर जब अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमें कार्य करना है तो हमारे लिए सबसे आवश्यक तत्व है 'समन्वय'। पार्टी संगठन में समन्वय स्थापित करने के बाद समाज की भिन्न–भिन्न समस्याएं लेकर कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया जिस तत्व से प्रेरित होनी चाहिए वह है 'सेवा' और 'संघर्ष'। सामाजिक संघर्ष से आगे बढ़ कर जब हम राष्ट्र के स्तर पर सोचते हैं तो वह तत्व जिसे सर्वाधिक महत्व देना चाहिए वह है समर्पण। क्योंकि हमारे व्यक्तिगत आचरण के संयम की शक्ति, संगठन की समन्वय से निकली सामूहिक शक्ति और

इसके द्वारा समाज में किये गये संघर्ष की ऊर्जा का अंतिम लक्ष्य अपने राष्ट्र यानी भारत माता के चरणों में समर्पण होना चाहिए।

यदि सारांश में कहें तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए संगठन का मूल मंत्र होना चाहिए –

व्यक्तिगत स्तर पर 'संयम'

संगठन के स्तर पर 'समन्वय'

सामाजिक स्तर पर 'सेवा' और 'संघर्ष'

राष्ट्र के स्तर पर 'समर्पण'।

अतः संयम, समन्वय, संघर्ष और समर्पण हमारा संगठनात्मक मूल मंत्र होना चाहिए।

मैं मानता हूं कि भाजपा के पास अत्यंत दुर्लभ और देश के सबसे समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह है। हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि समाज में हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कार्य पार्टी और संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला हो।

मैं इस संदर्भ में राम चरित मानस का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज खबर लेने लंका पहुंचे और उन्हें सीता जी दुखी नजर आई तो उन्होंने सीता जी को आश्वस्त किया कि कुछ समय के अंदर ही भगवान राम वानर सेना के साथ आयेंगे और सभी राक्षसों को मार कर आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलायेंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र वानर तो बहुत छोटे और कमजोर होते हैं और ये राक्षस बहुत शक्तिशाली और बलवान। अतः मुझे संदेह हो रहा है। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तब हनुमान जी ने अपना विराट और भयंकर स्वरूप की झलक दिखलाई और पुनः सामान्य रूप में आकर हाथ जोड़ कर विनम्रतपूर्वक यह कहा कि

'अबहिं मातु मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आयसु नहिं राम दुहाई'।

अर्थात हे माता, पूरी वानर सेना की बात छोडिए मैं अकेले आपको अभी मुक्त करा कर ले जाने में सक्षम हूं। परन्तु ऐसा करने से मेरी वानर सेना और मेरे आराध्य प्रभु श्रीराम का यश नहीं बढ़ेगा। इसलिए यह कार्य मैं उनके साथ ही मिलकर करूंगा।

अतः हम सभी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत क्षमतावान होने के बावजूद अकेले कुछ भी नहीं करना है बल्कि सामूहिकता के भाव से ही कार्य करने हैं। हनुमान जी के समान हमारा हर कार्य अपने पूरे संगठन और अपनी श्रद्धा के केन्द्र इस राष्ट्र के यश को बढ़ाने के लिए ही होने चाहिए।

आगामी चुनाव

मित्रों, 2013 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। कुछ ही महीनों बाद कर्नाटक का चुनाव है। इसी वर्ष नवम्बर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली का चुनाव है। संभवतः इसी वर्ष झारखंड का चुनाव भी हो सकता है। ये सभी राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव भी किसी समय हो सकता है। संभवतः लोकसभा चुनाव पहले की यह हमारी अंतिम कार्य परिषद है। स्पष्ट है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को यहां से जाकर अपने–अपने राज्यों में और लोकसभा की दृष्टि से देश भर में जुट जाना होगा। आगामी सभी चुनावों में विजय के संकल्प एवं अंत में दिल्ली विजय के संकल्प के साथ सभी अपने–अपने क्षेत्रों से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

“

हम सब कार्यकर्ताओं के लिए संगठन का मूल मंत्र होना चाहिए –

- **व्यक्तिगत स्तर पर ‘संयम’**
- **संगठन के स्तर पर ‘समन्वय’**
- **सामाजिक स्तर पर ‘सेवा’ और ‘संघर्ष’**
- **राष्ट्र के स्तर पर ‘समर्पण’।**

राजनाथ सिंह
अध्यक्ष, भाजपा

”

हमारे प्रेरणापुंज

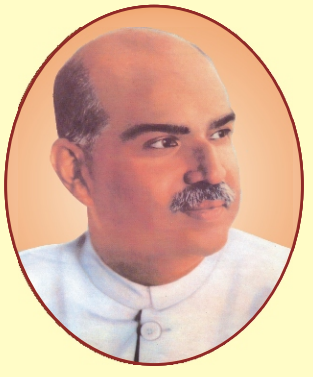

“जो राष्ट्र अपनी पूर्व उपलिब्धयों के प्रति गर्व अनुभव नहीं करता है अथवा उनसे प्रेरणा नहीं लेता है वह न तो अपने वर्तमान को सुधार सकता है और न ही अपने भविष्य की योजना बना सकता है। दुर्बल राष्ट्र महानता प्राप्त करने में सदैव असमर्थ रहता है।”

-डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी

“भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह सम्पूर्ण जीवन का, सम्पूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। टुकड़ों-टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं।

-पं. दीनदयाल उपाध्याय